

Current affairs summary for prelims

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण

संदर्भ: हाल ही में नई दिल्ली में वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदारी और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है ?

- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विवादों को हल करने के लिए स्थापित एक विशेष प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- यह जीएसटी कानूनों के तहत दूसरे स्तर की अपीलों को संबोधित करने, विवाद समाधान में एकरूपता की सुविधा प्रदान करने और मामले के समाधान प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करता है।
- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है, जो इसके संचालन के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करती है।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना:

- यह एक राष्ट्रीय स्तर की पीठ है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसमें अध्यक्ष (प्रमुख), एक न्यायिक सदस्य सिहत राज्य और केंद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले तकनीकी सदस्यों सिहत प्रमुख सदस्य शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए, केंद्र और संबंधित राज्य दोनों
 से दो न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों के साथ राज्य पीठों का गठन किया जाता
 है।

🕨 नियम, शक्तियाँ और कर्तव्य:

- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है।
- हालाँकि इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान व्यापक शक्तियां हैं, जो इसे सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करने, गवाह परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने और अदालत के आदेशों जैसे आदेशों को लागू करने में सक्षम बनाती है।
- इसके अलावा, ट्रिब्यूनल के पास कुशल और निष्पक्ष विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की स्वायत्तता है।

जीएसटी अपील शुल्क:

- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ अपील दायर करने के लिए, आवेदकों को कर, जुर्माना, ब्याज और जुर्माने सहित मूल आदेश में निर्धारित पूरी राशि जमा करनी होती है।
- विवाद के मामलों में, आवेदकों को अपीलीय प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी अपील शुल्क के रूप में उपरोक्त राशि का 20% भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य:

- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति को सावधानीपूर्वक संरचित
 किया गया है, जिसमें कई पात्रता मानदंड हैं जो इसके सदस्यों की क्षमता और
 विशेषज्ञता को सुनिश्चित करते हैं।
- राष्ट्रपति, ट्रिब्यूनल के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, या तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कानूनी कौशल और अनुभव के उच्चतम मानकों का प्रतीक होता है।
- न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों का चयन विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिससे ट्रिब्यूनल के भीतर एक विविध और जानकार संरचना सुनिश्चित होती

पात्रता और आयु मानदंड:

 जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए पात्रता और आयु मानदंड को सावधानीपूर्वक परिभाषित किया गया है, जिससे अपेक्षित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके।

7 May, 2024

 सदस्यों के लिए अधिकतम आयु अलग-अलग होती है, राष्ट्रपति को सत्तर साल में सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है, जबिक न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों को पैंसठ साल में सेवानिवृत्त होना चाहिए, जिससे ट्रिब्यूनल के भीतर नए दृष्टिकोण और प्रतिभा का संचार सनिश्चित हो सके।

जीएसटी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन:

- प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के फैसलों से असंतुष्ट करदाता अपील की तारीख के तीन महीने के भीतर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकते हैं।
- प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने और कुशल प्रसंस्करण की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवेदन के साथ लागू शुल्क और फॉर्म जीएसटी APL-05 संलग्न होना चाहिए।
- विवाद समाधान के लिए अपीलीय प्रक्रिया को समय पर अपनाने के लिए, निर्धारित समय सीमा से परे देर से जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डंपिंग रोधी शुल्क

संदर्भ: विगत तीन वर्षों में, वित्त मंत्रालय के एंटी-डंपिंग शुल्क ने अक्सर एक या दो घरेलू उत्पादकों के सामानों को लक्षित किया, मुख्य रूप से रसायन के क्षेत्रों में।

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, एंटी-डंपिंग शुल्क का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत चीन से आने वाले सामानों को लक्षित करता है।
- वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुशंसित मामलों में एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- व्यापार उपचार महानिदेशालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कई जांचों में एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी, जिसमें एक या दो उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया गया।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इन सिफारिशों के एक बड़े हिस्से को स्वीकार कर लिया, विशेष रूप से विशिष्ट कंपनियों के रासायनिक सामानों को लिक्षत किया।
- महामारी के बाद एंटी-डंपिंग शुल्क सिफारिशों की स्वीकृति दर में वृद्धि हुई है, जो डंपिंग से निपटने के लिए टैरिफ उपायों के प्रति सरकार के झ्काव को दर्शाता है।
- वर्तमान में चल रहे एंटी-डंपिंग मामलों में चीन, अमेरिका और रूस को लक्षित करने वाले एकमात्र उत्पादकों द्वारा उत्पादित सामान शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में चीन से भारत का आयात काफी बढ़ गया है, जो यहाँ के व्यापार असंतुलन को उजागर करता है।

🕨 डिम्पंग क्या है ?

परिभाषा: डंपिंग तब होती है, जब कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में,
 विदेशी बाजार में किसी उत्पाद को कम कीमत पर निर्यात करती है।

🍃 हंगिंग के लाभ

- बाजार में अनुचित कीमत वाले उत्पादों की बाढ़ लाने की क्षमता, संभावित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना।
- इस प्रकार की सब्सिडी विनिर्माण लागत से कम कीमत पर बेचने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है।

डंपिंग के नुकसान:

- समय के साथ सब्सिडी अस्थिर हो सकती है।
- व्यापार भागीदारों द्वारा बढ़ते प्रतिबंधों से निर्यात लागत में वृद्धि या आयात पर सीमा बढ़ सकती है।

🕨 डंपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय रवैया:

डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत डंपिंग तब तक कानूनी है जब तक यह साबित न हो जाए
 िक इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान होता है।







Current affairs summary for prelims

7 May, 2024

राष्ट्र आमतौर पर डंपिंग का मुकाबला करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए टैरिफ और कोटा का उपयोग करते हैं।

 डंपिंग के संबंध में व्यापार समझौतों का उल्लंघन चुनौतीपूर्ण और लागू करना महंगा हो सकता है।

व्यापार समझौता प्रतिबंध:

- अधिकांश व्यापार समझौतों में डंपिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- देशों के बीच विशिष्ट व्यापार समझौतों के बिना डंपिंग उल्लंघनों को लागू करना मुश्किल हो सकता है।

	Global Safeguards	Anti-Dumping measures	Countervailing Duties
Legal Basis	GATT Article XIX	GATT Article VI Agreement on Implementation of Article VI (AD Agreement)	WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
Objectives and Features	Create "breathing room" for domestic industry struggling with increasing imports MFN based import restrictions No allegations about unfair trade	Protect domestic industry from imports sold "at less than the normal value of the products" Departure from MFN principle It's about the "unfair" (pricing) practices of individual firms	Protect domestic industry from effects of another country's export subsidies actions Departure from MFN principle It's about the "unfair" (subsidies) practices of governments
Measures	Supplementary tariffs beyond bound MFN rates	Supplementary tariff beyond bound MFN rates targeted at particular foreign firms based on difference between the import price and the "normal" value	Supplementary tariff beyond bound MFN rates based on the value of the subsidy provided by the government of the exporting country
Criteria	Imports must be rising (absolute) Imports are causing "serious" injury to the domestic industry	Dumping, thus pricing below (1) production cost or (2) market price Imports are causing "material" injury to the domestic industry The comment of the comment of the domestic industry The comment of the comment of the domestic industry	Specific subsidies (financial contribution) by foreign governments that are exported Imports are causing "material" injury

कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal cancer)

संदर्भ: अमेरिका में फ्रेंड हचिंसन कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं ने हल ही में जीवाणु फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियेटम के एक अद्वितीय उपप्रकार की पहचान की है, जो कोलोरेक्टल कैंसर (सीआरसी) ट्यूमर में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है।

🕨 कोलोरेक्टल कैंसर (सीआरसी) घटना:

- सीआरसी भारत में पहचाना जाने वाला सातवां सबसे आम कैंसर है, वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक इसके मामलों में 20% की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक रूप से सीआरसी की कुल घटनाओं में गिरावट आई है, हालाँकि शुरुआती सीआरसी की घटनाओं में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है, खासकर 30 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में।

फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियेटम और सीआरसी:

- फ्रेड हचिंसन कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं ने सीआरसी ट्यूमर से जुड़े फ़्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियेटम के एक विशिष्ट उपप्रकार की पहचान की है।
- कैंसर का यह उपप्रकार संक्रमित होने पर चूहे की आंतों में कैंसर पूर्व संरचनाओं को प्रेरित करने के लिए पाया गया था।

🕨 आनुवंशिक विश्लेषण:

- आनुवंशिक विश्लेषण से प्रयूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियेटम के दो समूहों का पता चला,
 जिन्हें Fna C1 और Fna C2 कहा गया।
- सीआरसी ट्यूमर से जुड़े एफएनए सी 2 ने आंत में उपनिवेशण और चयापचय को स्विधाजनक बनाने वाले आनुवंशिक कारकों को प्रदर्शित किया।

चयापचय कारक:

- एफएनए सी 2 बैक्टीरिया में ऐसे जीन थे जो उन्हें मानव आंत में पाए जाने वाले विशिष्ट यौगिकों को चयापचय करने में सक्षम बनाते थे, जिससे सीआरसी ट्यूमर के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाती थी।
- इन चयापचय लक्षणों को मानव मल के नमूनों के विश्लेषण के माध्यम से मान्य किया
 गया था।
- संक्रमण के कारण: पिछली धारणा के विपरीत, विशिष्ट आनुवंशिक अनुकूलन के कारण, एफएनए बैक्टीरिया संभवतः जठरांत्र पथ के माध्यम से मुंह से आंत तक उतर सकता है।

🕨 माउस मॉडल अध्ययन:

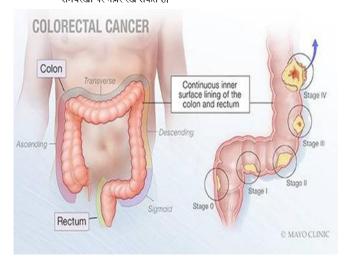
- माउस मॉडल में, Fna C2 बैक्टीरिया ने Fna C1 बैक्टीरिया की तुलना में एडेनोमा की अधिक घटनाओं को प्रेरित किया।
- एफएनए सी 2 उपचारित चूहों के आंतों के चयापचय प्रोफाइल में ट्यूमर की प्रगति के अनुरूप परिवर्तन दिखाई दिए।

मानव मान्यताः

- मानव रोगियों में गैर-कैंसर वाले ऊतकों की तुलना में सीआरसी ऊतकों में एफएनए सी2 समृद्ध पाया गया।
- सीआरसी रोगियों के मल के नमूनों में समान संवर्धन देखा गया, लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों में नहीं।

🕨 संभावित नैदानिक अनुप्रयोग:

- अध्ययन सीआरसी के लिए शीघ्र पहचान परीक्षण और लक्षित उपचार विकल्प विकसित करने का वादा करता है।
- भविष्य के शोध सीआरसी के लिए माइक्रोबियल हस्तक्षेप और निदान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, साथ ही शीघ्र निदान के लिए एफएनए सी2 बैक्टीरिया के उपनिवेशण समयरेखा पर नजर रख सकते हैं।





to the domestic industry





Current affairs summary for prelims

7 May, 2024

News in Between the Lines

हाल ही में, महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर में ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (टीएटीआर) से कुछ बाघों को सह्याद्रि में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में:

- ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रप्र जिले में एक वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है।
- इसकी स्थापना 1995 में 1955 में स्थापित ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और 1986 में स्थापित अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर की गई थी।
- यह बाघों की एक बड़ी आबादी का आवास है, 2010 की राष्ट्रीय जनगणना में लगभग 43 बाघ दर्ज किए गए हैं, जबिक 2023 में 93 हो गई है। जो इसे भारत के महत्वपूर्ण बाघ आवासों में से एक बनाता है।
- ताडोबा झील, कोलसा झील और ताडोबा नदी जैसे प्रचुर जल निकाय वन्यजीवों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- वनस्पति: रिजर्व में सागौन, ऐन, बीजा और बांस सिहत विविध वनस्पतियां हैं।
- जीव-जंत: जीव-जंत में बाघ, भारतीय तेंदुए, स्लॉथ भाल और गौर सहित अन्य प्रजातियाँ शामिल हैं।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने "ड्रिप प्राइसिंग" को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अलावा "छिपे हुए शुल्कों" का सामना करने की संभावना से आगाह किया है।

ड़िप प्राइसिंग के बारे में

- ड्रिप प्राइसिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति है जहां कंपनियां शुरू में किसी उत्पाद की कीमत का केवल एक हिस्सा दिखाती हैं और खरीद प्रक्रिया के दौरान बाद
 में अतिरिक्त शुल्क प्रकट करती हैं।
- छिपाना शामिल है।

इसमें बुकिंग शुल्क, सेवा शुल्क, रिसॉर्ट शुल्क या क्रेडिट कार्ड शुल्क, स्थानीय होटल कर या इंटरनेट सुविधा या कुछ सुविधाओं जैसे अनिवार्य शुल्कों को

- अतिरिक्त लागतों का प्रकटीकरण धीरे-धीरे खरीद के समय ही ग्राहक को किया जाता है, यह सामान्यतः आतिथ्य, यात्रा और ऑनलाइन भुगतान जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है।
- इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए आकर्षित करना है, जिससे अतिरिक्त लागतों का पता चलने पर उनके द्वारा लेनदेन रद्द करने की संभावना कम हो जाती है।
- उत्पाद या सेवा की कुल लागत के बारे में स्पष्ट जानकारी उपभोक्ता चाहते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को ड्रिप प्राइसिंग निराशाजनक लग सकती है, क्योंकि इससे
 तुलनात्मक खरीदारी करना जटिल हो जाता है।
- इिप प्राइसिंग का एक उदाहरण हवाई जहाज के टिकट की लागत है जो शुरू में कम दिखाई देती है, लेकिन इसमें सामान के शुल्क शामिल नहीं होते हैं, जिनका खुलासा बाद में खरीद प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।

हाल ही में, याक्कई हेरिटेज ट्रस्ट की एक टीम ने जीर्ण-शीर्ण श्री माधव पेरुमल मंदिर में और उसके आसपास पाए गए शिलालेखों पर एक अध्ययन किया। श्री माधव पेरुमल मंदिर के बारे में:

- श्री माधव पेरुमल मंदिर तमिलनाडु के इरोड जिले के भवानीसागर बांध क्षेत्र में स्थित है।
- यह 1,000 वर्ष से अधिक पुराना है और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- 1948 में भवानीसागर बांध के निर्माण के कारण मंदिर काफी हद तक जलमग्न रहा।
- यह मंदिर थॉन्ड्रीश्वरमुदियार (भगवान शिव) को समर्पित है।
- मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारत में प्रचलित द्रविड़ शैली को दर्शाती है, जिसमें जटिल नक्काशी और शिलालेख शामिल हैं।
- मंदिर में पाए गए शिलालेख पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र को दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यापार मार्ग से जुड़े होने का सुझाव देते
 हैं।
- ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में एक ट्रंक रोड थी और व्यापारी केरल के वायनाड और कर्नाटक के विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिए भवानी नदी और मोयार नदी को पार करते थे।
- मंदिर के आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है, जिसमें होयसल शासकों के शासनकाल और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान लड़ाई भी शामिल है।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व



ड़िप प्राइसिंग



श्री माधव पेरुमल मंदिर





Current affairs summary for prelims

7 May, 2024

अरेबियन ट्रैवल मार्केट का 31वां संस्करण 6 मई, 2024 को दुबई में शुरू हुआ।

अरेबियन ट्रैवल मार्केट के बारे में:

- अरेबियन ट्रैवल मार्केट (एटीएम) मध्य पूर्व में यात्रा और पर्यटन पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है, जो हर साल दुबई में आयोजित होता है।
- यह इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों पर्यटन क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए नेटवर्क बनाने, अपनी पेशकशों को प्रदर्शित करने और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- एटीएम का 31वां संस्करण दुबई में आयोजित हुआ, जिसमें 165 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हुए, और 2,300 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए।
- 31वें संस्करण का विषय है "नवाचार को सशक्त बनाना: उद्यमिता के माध्यम से यात्रा को बदलना", जो यात्रा उद्योग में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और यह 6 से 9 मई तक चलेगा।
- भारत ने एटीएम 2024 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने विविध सांस्कृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित किया और "कुल समर्स ऑफ इंडिया" अभियान के माध्यम से कम-ज्ञात ग्रीष्मकालीन स्थलों को बढ़ावा दिया।
- भारतीय मंडप, जिसे "अतुल्य भारत मंडप" के नाम से जाना जाता है, ने पर्यटकों की गहरी रुचि को आकर्षित किया, जिसमें राज्य पर्यटन बोर्ड और लक्जरी होटलों सहित 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 64% की वृद्धि के साथ, भारत के इनबाउंड पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय पुनरुद्धार हुआ।



POINTS TO PONDER

- हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग'ई 6 जांच लॉन्च की? **चीन**
- भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है? **नाइजीरिया**
- हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक
- हाल ही में 7वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 159



